

# अखण्ड भारत संदेश

[www.akhandbharatsandesh.net](http://www.akhandbharatsandesh.net)

नगर संस्करण प्रयागराज

मंगलवार 02 नवम्बर 2021

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट

## क्रियायोग संदेश

**क्रियायोग:** सच (Truth) को आँच नहीं। आँच अज्ञानता (अविद्या Ignorance) समय, दूरी व सापेक्षता की अनुभूति है जो समस्त दुःखों का कारण है। अध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सामान्य तरीके से जीवन जीने पर सच की अनुभूति के लिए व्याधि रहित लगभग दस हजार वर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन क्रियायोग अभ्यास से सच की अनुभूति एक ही जन्म में सम्भव है।

- प्राचीन उच्च मानव सभ्यता में वर्णित यज्ञ, वर्तमान में विश्व विष्वायत 'क्रियायोग' है।
- क्रियायोग अभ्यास वेदपाठ है, पूर्ण ज्ञान की अनुभूति है।
- क्रियायोग अभ्यास ईश्वर अनुभूति है।
- क्रियायोग अभ्यास अतीत, वर्तमान व भविष्य से जुड़ा है।
- क्रियायोग अभ्यास जीवन मृत्यु पर विजय है।

**खामी श्री योगी सत्यम्**  
**क्रियायोग आश्रम एवं**  
**अनुसंधान संस्थान**  
**प्रयागराज**

10 मिनट का अभ्यास 20 वर्ष का विकास

## पटना की हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी ने बचा ली थी हजारों की जान

पटना (एजेंसी)। आठ साल पहले 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तकालीन मुख्यमंत्री वर्षमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सूचीबूझ ने पटना में हजारों की जान बचाई थी। हम बात कर रहे हैं कि पटना में आयोजित हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का। धमाकों में छह लोगों की जान गई थी तथा 80 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अगर इस दौरान लाखों की भीड़ में भगदड़ मच जाती, तब भारी तादाद में जान-माल की क्षति होती है। लोगों ने बीमार गांधी की शरीर नहीं खोया। भगदड़ नहीं मची। इस अध्यक्षता में राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर रखी है। बातचीत अब भी जारी है। इसके अलावा उत्तरांचल ने भी इस में संज्ञान लिया है। बैंडर बंद होने से आवागमन करने वाले लोगों के साथ स्थानीय निवासी और व्यापारी बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रास्ता रोक बैठे लोगों का स्थानीय लोगों, व्यापारियों और इस प्रकार से आवागमन करने वाले आम लोगों की यह समस्या समझनी चाहिए और बातचीत के लिए आगे आगा चाहिए। उहोंने कहा कि क्रियायोग का सम्बन्ध केंद्र सरकार से है हरियाणा का इनसे कोई लेना देना नहीं है अलवता सरकार इन कानूनों का समर्थन करती है। एक सवाल पर उहोंने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग से हो रही भवित्वों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। उनकी सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के गत सात साल में 83 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं।



मामले में एनआइए कोर्ट ने आतंकियों को सजा दे दी है। कोर्ट पहले ही आतंकी हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्हाफ़, उमर सिंहिकी, फिरोज असलम एवं इमितायज आलम सहित नौ नों दोषी करार दे चुका था। इस मामले के 10 आरोपितों में से एक फकरहीन

रिहा कर दिया गया है। पटना के गांधी मैदान में साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए एंडोर्न की हुंकार रैली थी। इसे संबोधित करने वाले भारतीय जनता पार्टी (जेपी) की ओर से एनडीए के प्रधानमंत्री चेहरा (दश ईम) बनाए गए गुजरात के तकालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ थे। उहोंने सुनने के लिए गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में लोगों की भारी भीड़ थी। उनका संबोधन सुनने के लिए लोग ट्रैकों व बसों भी आ रहे थे। इस कारण कुछ किलोमीटर दूर स्थित पटना जवाहर से गांधी मैदान तक सड़कों पर भी भारी भीड़ थी। हर टरफ लोग ही लोग थे। इनी बीच लगातार यह करते रहे कि उत्साह में पटाखे न छोड़ कि मैदान के बाहर भी गैलरी होगी। लूटोने वाले भी गेट के आसपास ही हुए थे। ऐसे में गैलरी की योजना बनाई है। यह एफिल टॉवर से बैहतर पर्यटक आकर्षण होगा। इसमें विशेष स्थान के लिए एक रेस्टरां और आर्ट गैलरी होगी।

गडकरी बोले- एफिल टावर से भी अधिक आकर्षक होगा गोवा का यह पुल, पार्किंग की भी व्यवस्था

पणजी (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि गोवा में जुआरी नदी पर बनने वाले पुल पर प्रस्तावित ब्लूडॉग गैलरी फांस में परिस के प्रसिद्ध एफिल टॉवर से बैहतर आकर्षक होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पणजी-मडगांव राजमार्ग पर मौजूदा पुल के सामानांतर बनाव वाले पुल के आगे साल सिवंबर तक पुरा होने की उमीद है, लेकिन इससे पहले कम से कम एक ठेने खोलेने का प्रयास किया जा रहा है। गडकरी ने कहा, ठजुआरी पुल पर कम चल रहा है। हमने इस पुल के द्विस्थिती के रूप में दो टारों को निर्माण करके एक देखने वाली नीताओं ने भगदड़ रोकने को मंच से ही कमान संभाली। वे लगातार यह करते रहे कि उत्साह में पटाखे न छोड़ कि मैदान के बाहर भी गैलरी होगी। लूटोने वाले भी दर बढ़ाव देने की ओर आयोगी नीताओं ने भगदड़ रोकने को मंच से ही नेताओं का आवाज अनहोनी की आवाज की जाती रही, मारने वालों से अनजान लोग शांत बने रहे।



धनतेरस व दीपावली के शुभ अवसर पर जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।



श्यामकान्त शुक्ला उर्फ लहरी भैया

मिर्जापुर, प्रयागराज जनपद के एक मात्र लोक प्रिय समाजसेवी कोरोना के साथ - साथ सामाजिक, धार्मिक एवं स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों में विशेष योगदान के लिए समर्पित व्यक्तित्व समाज सेवा करना ही दृढ़ संकल्प

शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, शिक्षार्थियों एवं सम्मानित जनपदवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रमन मिश्र  
अध्यक्ष  
प्रबंध समिति

प्रो० मनोज मिश्र  
प्राचार्य  
एमडीपीजी कालेज, प्रतापगढ़

आनंद पाण्डेय (एडवोकेट)  
मंत्री  
प्रबंध समिति

समरत जनपद वासियों को धनतेरस, दीपवली की हार्दिक शुभकामनाएं

**CHANDRA SHEKHAR SINGH GROUP OF INSTITUTIONS**

- 1 HIGH RESULTS
- 2 EXCELLENT PLACEMENT RECORD
- 3 DRUG INSPECTOR, GOVT. ANALYST, HOSPITAL PHARMACIST
- 4 GPAT ACADEMIC ATMOSPHERE
- 5 PRACTICAL ORIENTED

**REGISTRATION/ ADMISSION OPEN**



**B.A.M.S. (5½ Years)**

Approved By CCIM, New Delhi  
(Ministry of Ayush, Govt. of India)

Affiliated to Prof. Rajendra Singh (Raju Bhaiya) Rajya Vishwavidyalaya, Prayagraj U.P.

**B. PHARMA (4 Years)**

College Code - 552

Approved by P.C.I. & A.I.C.T.E. New Delhi

Affiliated to A.K.T.U. Lucknow U.P.

**DIPLOMA COURSE OFFERED**

- DIPLOMA IN PHARMACY (Ayurved 2 Years)
- G.N.M. (Ayurved 3½ Years)
- (Affiliated To Ayurvedic & Unani Tibbi Chikitsa Paddhati Board Lucknow U.P.)
- CCYP (Certificate Course in YOGA Practice)

**HOSTEL FACILITY AVAILABLE**

16 KM AWAY FROM PRAYAGRAJ RAILWAY STATION AT ALLAHABAD-KANPUR HIGHWAY

10 KM FROM AIRPORT BAMRAULI

GT ROAD NEAR THANA PURAMUFTI, (KOILAH) KAUSHAMBI (U.P.)

**HELPLINE** (AYURVED) 7524037425  
(PHARMACY) 9329582143, 9300640664, 9936764324

[www.cscp.co.in](http://www.cscp.co.in) | [www.cssas.org](http://www.cssas.org) | [cssas.allahabad@gmail.com](mailto:cssas.allahabad@gmail.com) | [cscp.allahabad@gmail.com](mailto:cscp.allahabad@gmail.com)









# सम्पादकीय

## धरती की खातिर

पर्यावरण बचाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी दुनिया के तमाम छोटे-बड़े देश ब्रिटेन के गूसगो में जूटे हैं। सीओपी (कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज) 26 सम्मलेन में सभी देश एक बार फिर इस मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि धरती का पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दशकों में वैश्विक तापमान और बढ़ेगा। इसलिए अगर दुनिया अब भी नहीं चेती तो इकीसर्वी सदी को भयानक आपदाओं से कोई नहीं बचा पाएगा। गूसगो में हो रहे इस पर्यावरण सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब पर्यावरण बिगाड़ने के जिम्मेदार देशों को भविष्य का खाका तैयार करना है। उन्हें बताना है कि कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए वे क्या करने जा रहे हैं। धरती को बचाने के प्रयासों में सबसे बड़ी मुश्किल यह आ रही है कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन के लिए गरीब मुल्कों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। इसलिए सम्मेलनों का मकसद कभी पूरा नहीं पाता।

दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो जलवायु संकट की मार नहीं झेल रहा होगा। हालांकि यह संकट कोई एकाध दशक की देन नहीं है। पिछली दो सदियों में हुए औद्योगिक विकास की अति ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर पिछले करीब पांच दशकों में यह संकट कहीं ज्यादा गहराया है। इसी का नतीजा है कि अब हम बैमौसम की बारिश, बाढ़, सूखा, धूधकरते जंगल, पिघलते ग्रेशियर, समुद्रों का बढ़ता जलस्तर और इससे तटीय शहरों और द्वीपों के फूबने के खतरे और बढ़ते वायु प्रदूषण जैसे संकट झेल रहे हैं। कुछ महीने पहले यूरोप के देशों में जैसी बाढ़ आई, वैसी तो कई सदियों में नहीं देखी गई। अमेरिका सहित कई देशों में जंगलों में आग की घटनाएं वायुमंडल में कितनी कार्बन आक्साइड छोड़ रही होंगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ये घटनाएं हमें चेतावनी दे रही हैं। पर हैरानी की बात की बात यह कि दुनिया के ताकतवर मूल्क सम्मेलनों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। धरती को बचाने के लिए काम किसी एक देश को नहीं, बल्कि सबको मिल कर करना है। इसलिए यह जिम्मेदारी सबकी बनती है कि सम्मेलन में जो सहमति बने और समझौते हों, उन पर ईमानदारी से अमल हो। पर व्यवहार में ऐसा देखने में आता कहाँ है! अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य दूसरे देशों पर तो थोप रहे हैं, पर वही इस दिशा में बढ़ने से करनी काट रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देश अपने यहां कोयले से चलने वाले बिजलीघरों को बंद कर नहीं कर रहे। यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका 2017 में पेरिस समझौते से सिर्फ अपने हितों के कारण पीछे हट गया था। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित और विकासशील देशों के लक्ष्य भी स्पष्ट होने चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकासशील देशों को जितना पैसा मिलना चाहिए, वह मिल नहीं रहा। ऐसे में वे अपने यहां उन योजनाओं को लागू ही नहीं कर पा रहे, जिनसे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलनों की सार्थकता तभी है जब इसे अमीर बनाम गरीब न बनाया जाए। सारे देश मिल कर साझा एंजडे पर बढ़ें। वरना पर्यावरण बिगाड़ने का ठीकरा गरीब देशों पर फूटता रहेगा और धरती का खतरा बढ़ता जाएगा।

# मुद्रास्फीति के बड़े इंस्टके के लिए तैयार रहें

डॉ. अजीत राना

मुद्रास्फीतिजन्य मंदी से बचने के लिए मांग की स्थिति अभी मजबूत हो सकती है। इसका संकेत बैंक ऋणों में वृद्धि से मिलता है। रोजगार भर्ती, अच्छी नौकरियों और श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक धीमा संकेतक है। यह कुछ ऐसा है जिसे बारीकी से देखा जाना चाहिए। यदि आधारभूत संरचना के खर्च और श्रम केन्द्रित नियर्यात क्षेत्रों, सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार में वृद्धि दिखती है तो मुद्रास्फीति को कुछ अंशों में कम किया जा सकता है। अक्टूबर के महीने में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ज्यादातर कंपनियां सिंतंबर में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करती हैं। अच्छी खबर यह है कि कम से कम बड़ी कम्पनियों में वास्तव में अर्थिक गति अच्छी है तो इस दिवाली और क्रिसमस तिमाही में भी अच्छा मुनाफ़ा नजर आना चाहिए। फिर भी, चिंता का साया मंडरा रहा है और कई कंपनियों के अधिकारियों ने इस चिंता को जाहिर किया है जिन्होंने सिंतंबर में समाप्त तिमाही में अपने अच्छे लाभ की घोषणा की है। शैम्पू से लेकर डिटर्जेंट व आइसक्रीम तक सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के अग्रणी निर्माता यानी साबुन, तेल, त्वचा की देखभाल और खाद्य उत्पाद बनाने वाली कम्पनी हेंदुस्तान यूनिलीवर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने चेतावनी दी है कि इस समय इनपुट लागत में वृद्धि की गति विगत एक दशक से अधिक समय में सबसे तेज है।

धारणा करता हा अच्छा खबर यह हा एक कम स कम बड़ा कम्पनीया माकॉर्पोरेट मुनाफे में नाटकीय रूप से सूधार हो रहा है। बढ़ी हुई मांग के कारण ज्यादा कीमत मांगी जा रही है जिसकी वजह से लाभ बढ़ रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं (यानी खाद्य पदार्थ और धार्गा), वाशिंग मशीन, टोस्टर, घरों में प्रयुक्त सजावटी सामानों, फैशन, धातुओं, सीमेंट, निर्माण सामग्री, रसायनों जैसे कमोडिटी जैसे क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियों के मामले में यह बात सच है। ई-कॉमर्स साइट्स पर इनकी बिक्री फल-फूल रही है। यहां तक कि बैंक भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने इस तिमाही को सबसे अच्छा बताया है। ऑटोमोटिव सेक्टर का प्रदर्शन भी अच्छा है। महंगी और लकड़ी चार पहिया वाहनों की मांग ज्यादा तेजी से बढ़ रही है जबकि दो पहिया वाहनों की मांग में गिरावट देखी गई है। यह के शेष वसूली को दर्शाता है। (के शेष इकोनॉमिक रिकवरी तब होती है, जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी होती है। के-शेष इकोनॉमिक रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं।) के-शेष रिकवरी के ऊपरी हिस्से यानी उच्च आय, शहरी ब्रैकेट और निचले हिस्सा कम आय वाले परिवर्गों व ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के लाभ उठाने का प्रतीक है। के-शेष का ऊपरी हिस्सा आबादी के उस खंड का भी प्रतिनिधि है जिसे शेयर बाजार में धन वृद्धि से बेहद लाभ हुआ है।

# सुन लो दुनिया के हुक्मरान ! ना बदला था, ना बदला है और ना बदलेगा तालिबान

अभी रूस ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर वार्ता की मेजबानी की। इसमें तालिबान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने भी बात की। भारत ने सहायता का आश्वासन भी दिया। चीन ने युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान को 10 लाख अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराए हैं। अफगानिस्तान के कज्जे के दो माह बाद भी तालिबान का रवैया वही है, जो बीस साल पहले था। खस्ता हाल और भूखे देश को चलाने के लिए उसे मदद चाहिए, वह भी अपनी शर्तों पर। अफगानिस्तान के हालात को लेकर दुनिया भर के देश चिंतित हैं। सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान में विकास हो। बाकी जनता की समस्याएं हल हों। हालात सामान्य हों। लोगों को भरण-पोषण की चीजें उपलब्ध हों। पर अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान अपने एजेंडे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका क्रूरता का घेराव वैसा ही है जैसा बीस साल पहले था। उसने उस पर कोई मुख्योंता नहीं लगाया। कोई आवरण नहीं ओढ़ा। उनको दुनिया से अपने लिए मदद चाहिए, वह भी अपनी शर्तों पर। उन्हें न मानवता से कुछ लेना है, न मानव समाज से। अभी रूस ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर वार्ता की मेजबानी की। इसमें तालिबान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने भी बात की। भारत ने सहायता का आश्वासन भी दिया। चीन ने युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान को 10 लाख अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि चीन ने यह आर्थिक मदद दी है और मानवीय मदद (विशेष रूप से भोजन और दवाओं के लिए) के तौर पर पांच लाख अमेरिकी डॉलर और उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। अफगानिस्तान की आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। वहाँ भोजन का संकट

# सुन लो दुनिया के हुक्मरान

अशोक मधुप है। पेट भरने के लिए लोग अपनी बेटियां तक बेच रहे हैं। वहां न जरुर का सामान है, न ठंड से बचने के लिए कपड़े। इस हालात से दुनिया अफगानिस्तान की जनता के बारे में सोच रही है। चिंता कर रही है किंतु अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान का रवैया कुछ और ही कहा है। उनके आचरण से लगता है कि पिछले 20 साल में उन्होंने अपने कोई बदलाव नहीं किया। उनका एजेंडा वही है। वे कट्टर इस्लामिक धर्मी हटने को तैयार नहीं हैं। सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान मान्यता पाने के लिए सभी धर्मी को साथ लेकर चलने का दावा किया था लेकिन अब अत्यसंख्यकों के लिए वहां सुरक्षा हालात बद से बदलतर हो जा रहे हैं। तालिबान ने वहां रहने वाले सिखों को फरमान जारी कर हुए कहा है कि या तो इस्लाम कुबूल कर लो या फिर देश छोड़ दो। इतनी ही नहीं इस्लाम कबूल न करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तालिबान ने सत्ता संभालते ही जेल में बंद सभी कैदियों को रिहा कर दिया। अब ये रिहा कैदी उन्हें सजा देने वाले न्यायधीश को खोज रहे हैं न्यायधीश अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। अफगानिस्तान से भागी महिला जज ग्रीस में शरण लिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद लगा था कि चीन, पाकिस्तान और रूस तथा आसपास कुछ इस्लामिक देश उसे तुरंत मान्यता दे देंगे। पाकिस्तान तो इस अभियान

अशोक मधुप

के लिए सक्रिय भी हुआ। इतना सब होने के दो माह बाद भी अब तक एक भी देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दे सका। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अमेरिका से वार्ता में उसने वायदा किया था कि वह देश में मौजूद सभी संगठनों को साथ लेकर सरकार बनाएगा। अफगानिस्तान से सटे देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति रहे। वहां की जनता को जरूरत की चीज़ आराम से मिलती रहे, किंतु यह सब आपके, मेरे चाहने और सोचने से होने वाला नहीं है। उसके लिए तो तालिबान को ही अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा। उसे ही अपने को इस योग्य बनाना होगा कि दुनिया स्वयं सहायता के लिए आगे आए।

अपने बच्चों को मौका देते हैं और दूसरों को सजा

उमेश कुमार गुप्ता

बीते सितंबर महीने में राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग ने एक 15 वर्षीय नाबालिग को नशीली दवा रखने के आरोप में सुधार गृह के

# पेट्रोल-डीजल दाम बढ़ने के पीछे की असल वजह

जाहिद खान

बिंगाड़े हैं। मोदी सरकार ने जब से केन्द्र की सत्ता संभाली है, पेट्रोल पर उत्पाद कर तीन गुना बढ़ गया है। साल 2014 में पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपये थी, जो अब 32 रुपये से अधिक है। वहीं डीजल पर तो उत्पाद कर में दस गुना इजाफा हुआ है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपये से बढ़कर 32 रुपये के पार पहुंच गई है। इसी साल मार्च 2021 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को अपने लिखित जवाब में जो आंकड़े पेश किए, उसके मुताबिक बीते छह सालों के दौरान पेट्रोल और डीजल से होने वाली केंद्र सरकार की कमाई में करीब 300 फीसदी का इजाफा हुआ है।

पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिफ च्याही एक अकेला कारण नहीं है। केन्द्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के अलाग इन पर राज्य सरकारें, वैल्यू ऐडेट टैक्स यानी वैट भी लगाती हैं। यह वैट भी कोई कम नहीं। इसी साल 26 जुलाई को केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बताया था कि सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल पर लेती है। जो 31.55 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डीजल पर सबसे ज्यादा वैट राजस्थान सरकार लेती है, जो 21.82 रुपये प्रति लीटर है। राज्य सरकारें वैट के साथ-साथ

कई बार कुछ अन्य टैक्स भी जोड़ देती है। मसलन ग्रीन टैक्स, टाउन रेट टैक्स वैगरह-वैगरह। एक लिहाज़ से कहें, तो पेट्रोल और डीजल केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए कमाई का मोटा ज़रिया बने हुए हैं। बीते सात सालों में इनसे सरकारों ने 22 लाख करोड़ रुपये की कमाई की है। अगर केन्द्र और राज्य सरकारें चाहें, तो उत्पाद कर और वैट को कम करके जनता को एक बड़ी राहत दे सकती है। लेकिन इस दिशा में कोई किसी भी तरह की पहलकदमी नहीं कर रहा। केन्द्र में जब संप्रग सरकार सत्ता में थी, तो बीजेपी नेता अक्सर सरकार को पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती के लिए, उत्पाद कर को कम करने की सलाह देते थे। लेकिन जब यही मांग विपक्षी पाटियां उनसे कर रही हैं, तो मोदी सरकार को जैसे सांप सूंध गया है। जब भी सरकार से यह मांग होती है, वह बढ़ते राजकीयीय घाटे की दुहाई देने लगती है। उसकी ओर से तरह-तरह के कुर्कत आने लगते हैं कि इसी शुल्क की वजह से जनता को फ़ी कोरोना वैक्सीन और राशन आदि मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के पीछे मोदी सरकार, एक तर्क और देती है। यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तेल कंपनियों को ऑयल बॉण्ड जारी किए थे। इन बॉण्ड के भुगतान के वास्ते उसे मजबूरी में जनता से ज़्यादा एक्साइज इयर्टी लेना पड़ रही है। सरकार की इस ढलील में कितनी सच्चाई है, इसकी भी पड़ताल ज़रूरी है। इसके लिए हमें आज से दो दशक पीछे जाना होगा। तेल की बढ़ती कीमतें आम जनता पर बोझ न बर्ने, इसके लिए केंद्र सरकार पहले सब्सिडी दिया करती थी। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें चाहे जो भी हों, देश में सरकारें अपने मुताबिक उसे कंट्रोल करती थीं। इसके लिए पूर्वतरी सरकारों ने तेल कंपनियों को ऑयल बॉण्ड जारी किए। सिफ़ यूपीए सरकार ने ही नहीं, बीजेपी के नेतृत्व में राजग सरकार ने भी यह काम किया। ऑयल बॉण्ड होते क्या हैं

इसे भी जानना लाजिमी है। ऑयल बॉण्ड वो सिक्योरिटी होती है, जिसका सरकारें नकद सब्सिडी के बदले तेल कंपनियों को दिया करती है। ये बॉन्ड अमूमन लंबी अवधि के होते हैं। तेल कंपनियों को इन पर ब्याज़ भी चुका जाता है। अपने राजकोष पर बोझ़ डाले गौर केंद्र की यूपीए सरकार ने सन् 2005 से लेकर 2010 तक तेल कंपनियों को ऑयल बॉण्ड जारी किया। ताकि तत्कालीन सरकार को नकद नहीं खर्च करना पड़े। लेकिन दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी के बाद, जब यूपीए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ावा दिया, तो ऑयल बॉण्ड जारी किया जाना जून, 2010 से खत्म हो गया। सरकारी नियंत्रण समाप्त करने का अर्थ कि जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, देश में तेल कंपनियां उसी हिसाब से उनकी कीमतें बाज़ार में तय करेंगी। सरकार इस फैसले के बाद तेल की कीमतों का बोझ़ सीधे नागरिकों के कंधों पर लगा गया। साल 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आए। मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार से दो कदम और अब बढ़ते हुए, उसी साल अक्टूबर में डीज़ल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया।

यूपीए सरकार के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉण्ड के भुगतान की मोदी सरकार और उसके तमाम सिपहसालार बार-बार दुहाई देते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज़ इयूटी से सरकार के खजाने में कितना पैसा आ रहा है, इसके बारे में देशवासियों को कुछ नहीं बतलाते। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल यानी 2014-15 के दौरान एक्साइज़ इयूटी से पेट्रोल पर 29,279 करोड़ रुपये और डीजल पर 42,881 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसी साल मार्च में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप लिखित जवाब में बताया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से कमाई बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपए हो गई है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज़ इयूटी सरकार के खजाने में बेशुमर ऐसा आ रहा है, तो दूसरी ओर सरकार ऑयल बॉण्ड का रोना रो रही है। जबकि हिसाब लगाएं, तो ऑयल बॉण्ड का सरकार पर कोई ज़्यादा बोझ नहीं है। सरकार को 1.31 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बॉण्ड के मूलधन के रूप में तेल कंपनियों को देने हैं, इस ब्याज़ को भी यदि जोड़ लें, तो यह रकम दोगुनी हो सकती है। यानी उसका देनदारी तकरीबन 2.62 लाख करोड़ रुपये होगी। जो आंकड़ा निकलता है आ रहा है, वह मोदी सरकार द्वारा दस महीने में टैक्स से हुई कमाई से रहता है। इस बात से यह साबित होता है कि यूपीए सरकार के दौरान जारी रखे गए ऑयल बॉण्ड, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए करतई ज़िम्मेदार नहीं। मोदी सरकार की नीतयत में ही कहीं खोट है। इस बारे में वह लगातार ग़लतबयानी कर देशवासियों को गुमराह करने का काम कर रही है। जबकि हकीकत कुछ और है। सरकार को देशवासियों के दुःख-दर्द, तकलीफों जरा सा भी ख्याल होता, तो वह फौरन पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज़ इयूटी कम करती। जिसका सीधा-सीधा असर पेट्रोल-डीजल के दामों पर पड़ता है और देशवासियों को मंदगार्ड से बड़ी गड़त प्रिलगी।



